

जुलाई 2022

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- **वित्त**
 - वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो
 - अंतरराष्ट्रीय व्यापार नपिटान
 - सोशल स्टॉक एक्सचेंज
- **खेल**
 - राष्ट्रीय डोपिंग रोधी वधियक, 2021
 - मध्यस्थता वधियक, 2021
- **ऊर्जा**
 - अक्षय खरीद और ऊर्जा भंडारण दायित्व
- **शिक्षा**
 - उच्च शिक्षण संस्थानों की समीक्षा
- **उपभोक्ता मामले**
 - सेवा शुल्क लगाने के नषिध पर दशिया-नरिदेश
 - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधकिरण (CCPA)
 - गुणवत्ता नयित्रण ककष
- **पर्यावरण**
 - प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016

वित्त

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो

कैबिनेट नयिकुत्त समिति (Appointments Committee of the Cabinet- ACC) ने **बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB)** के स्थान पर **वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB)** की स्थापना के लयि एक सरकारी प्रस्ताव पारति कयिा है ।

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB):

परचिय

- वित्त मंत्रालय ने एक वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) का गठन कयिा ।
- FSIB वित्तीय सेवा संस्थानों के बोर्ड में पूरणकालकि नदिशकों और गैर-कार्यकारी अधयकषों के रूप में नयिकुत्त के लयि व्यक्तयिों की सफिरशि करेगा ।
- वित्तीय सेवा संस्थानों में सार्वजनकि कषेत्र के बैंक और सार्वजनकि कषेत्र के बीमाकर्त्ता शामिल हैं ।
- FSIB बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की जगह लेता है जसिके पास समान जनादेश था ।

संयोजन

- FSIB में एक अंशकालकि अधयकष, चार पदेन सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नामति छह अंशकालकि सदस्य होंगे । पदेन सदस्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - वित्तीय सेवा वभिग के सचवि ।
 - सार्वजनकि उद्यम वभिग के सचवि ।

- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ।
- भारतीय रज़िर्व बैंक के एक डपिटी गवर्नर ।
- मनोनीत सदस्यों को पूरव बैंकरों, पूरव नियामकों, शक्तिषावर्दों और व्यावसायिक व्यक्तियों में से चुना जाएगा ।

FSIB के कार्य:

- नदिशकों और अध्यक्षों के रूप में नयुक्तों के लयि व्यक्तियों की सफिराशि करने के अलावा, FSIB केंद्र सरकार को नमिनलखिति पर सलाह देगा:
 - वतितीय सेवा संस्थानों की वांछति परबंधन संरचना ।
 - वतितीय संस्थानों में नदिशकों के लयि आचार संहति और नैतिकता का नरिमाण एवं परवर्तन ।
 - ऐसे संस्थानों को व्यावसायिक रणनीति और पूंजी जुटाने की योजना वकिसति करने में मदद करना ।
 - परबंधन कर्मियों के लयि प्रशक्तिषण कार्यक्रम वकिसति करना ।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नपिटान

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने तत्काल परभाव से रुपए (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुवधि के लयि एक तंत्र स्थापति कयिा है ।

- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने भारतीय रुपए में नरियात और आयात के चालान, भुगतान एवं नपिटान की अनुमति दी है ।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते के परमुख तत्त्व:

- भारतीय नरियात पर जोर देते हुए वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना ।
- भारतीय रुपए में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करना ।
- नई व्यवस्था लागू होने तक अधिकृत डीलर बैंकों को RBI से मंजूरी लेनी होगी ।
- इस व्यवस्था के तहत सभी नरियात और आयात का मूल्यवर्ग और चालान रुपए में कयिा जाएगा ।
- बाज़ार दो व्यापारिक भागीदारों के बीच मुद्रा वनिमिय दर का नरिधारण करेगा ।

समिति की परमुख टपिपणयिों और सफिराशें:

वैधानिक जमा से छूट:

- 1 जुलाई, 2022 से पहले बैंकों को सभी वदिशी मुद्रा अनविासी बैंक और अनविासी (बाहरी) रुपया (INR) जमा को शुद्ध मांग और सावधिदेनदारयिों (NDTL) के तहत शामिल करना आवश्यक था ।
- NDTL का उपयोग उन जमाराशयिों के अनुपात की गणना करने के लयि कयिा जाता है जनिहें बैंकों को नकद आरकषति अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के तहत बनाए रखना होता है ।
 - CRR नकद आरकषति राशि है जसि बैंकों को RBI के पास रखना होता है । SLR जमा की वह राशि है जो बैंकों को सोने और सरकारी परतभूतयिों जैसी कुछ संपत्तयिों में अनविार्य रूप से नविश करनी होती है ।
- RBI ने अब 1 जुलाई, 2022 से 4 नवंबर, 2022 तक जुटाई गई वृद्धशील वदिशी मुद्रा जमा को CRR और SLR शर्तों से छूट दी है ।

जमा पर ब्याज़:

- पहले FCNR(B) जमाराशयिों पर ब्याज़ दरें एक उच्चतम सीमा के अधीन थीं जो एक बेंचमार्क ब्याज दर के आधार पर नरिधारति की जाती थी ।
- इसी तरह INR जमाराशयिों पर ब्याज़ दरें घरेलू रुपया सावधि जमाओं की तुलना में अधिक नहीं हो सकती हैं ।
- 7 जुलाई, 2022 और 31 अक्तूबर, 2022 के बीच FCNR(B) और INR जमा से संबंधति बैंकों की ब्याज़ दर में बदलाव को इन नयिमों से छूट दी जाएगी ।

ऋण में FPI नविश:

- सरकारी परतभूतयिों और कॉरपोरेट बॉण्ड में वदिशी पोर्टफोलयिो नविशकों (FPI) के लयि नविश चैनलों में शामिल हैं:
 - मध्यम अवधि की रूपरेखा (MTF)
 - फुली एक्सेसबिल रूट (FAR) ।
- FAR के तहत FPI बनिा कसिी नविश सीमा के नरिदषिट सरकारी परतभूतयिों में नविश कर सकते हैं ।
- नरिदषिट परतभूतयिों की वर्तमान सूची में 5 वर्ष, 10 वर्ष और 30 वर्ष की अवधि वाली सभी केंद्र सरकार की परतभूतयिों शामिल हैं ।
- RBI ने अब 7 वर्ष और 14 वर्ष की अवधि के साथ जारी सभी नई सरकारी परतभूतयिों को शामिल करने के लयि इस सूची का वसितार कयिा है ।
- MTF के तहत कॉरपोरेट ऋण और सरकारी परतभूतयिों दोनों के लयि अधिकतम 30% FPI नविश एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परपिक्वता वाले उपकरणों में हो सकता है ।
- FPI द्वारा सरकार और कॉरपोरेट ऋण में कयिे गए नविश को 31 अक्तूबर, 2022 तक इस सीमा से छूट दी जाएगी ।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज

[भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड \(SEBI\)](#) ने [सोशल स्टॉक एक्सचेंज \(SSE\)](#) के लिये नयामक ढाँचे को अधिसूचि कयि।

प्रमुख वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

■ **धन जुटाने के लिये पात्र संस्थाएँ:**

- गैर-लाभकारी और लाभकारी सामाजिक उद्यम SSE के माध्यम से धन जुटा सकते हैं।
- एक सामाजिक उद्यम को नरिदषिट गतिविधियों में शामिल कयि जाना चाहिये जसिमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - भूख, गरीबी, कुपोषण और असमानता का उन्मूलन।
 - शकिषा, रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देना।
 - स्वास्थय देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षति पेयजल उपलब्ध कराना।
 - ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिये आजीविका को बढ़ावा देना।
- ऐसे उद्यमों को उन अवकिसति या अलपवकिसति आबादी वाले खंड या क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रति करना चाहिये जिन्होंने वकिस प्राथमकिताओं में नमिन स्तरीय प्रदर्शन कयि है।
- कुछ नकियाय जैसे कॉरपोरेट फाउंडेशन, राजनीतिक या धार्मिक संगठन और पेशेवर या व्यापार संघ सामाजिक उद्यम के रूप में वर्गीकृत होने के पात्र नहीं होंगे।

■ **धन जुटाने के तरीके:**

- गैर-लाभकारी संगठन नमिनलखिति के माध्यम से धन जुटा सकते हैं:
 - संस्थागत और गैर-संस्थागत नविशकों को जीरो कूपन जीरो प्रसिपिल इंस्ट्रुमेंट्स जारी करक
 - म्यूचुअल फंड के माध्यम से डोनेशंस।
- जीरो कूपन जीरो प्रसिपिल इंस्ट्रुमेंट्स की परपिकवता पर कोई कूपन भुगतान या मूलधन पुनर्भुगतान नहीं होगा।
- उनके पास एक करोड़ रुपए का न्यूनतम नरिगम आकार होगा।
- लाभकारी सामाजिक उद्यम नमिनलखिति के माध्यम से धन जुटा सकते हैं:
 - इक्विटी शेयर जारी करना।
 - ऋण प्रतभूतियाँ जारी करना।

खेल

राष्ट्रीय डोपगि रोधी वधियक, 2021

[लोकसभा](#) ने राष्ट्रीय डोपगि रोधी वधियक, 2021 पारति कयि, जो राष्ट्रीय डोपगि रोधी एजेंसी (NADA) के लिये वैधानिक ढाँचा तैयार करने का प्रयास करता है।

- यह वधियक खेलों में डोपगि को प्रतबिंधति करने का प्रयास करता है और एक वैधानिक नकियाय के रूप में राष्ट्रीय डोपगि रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है।
- डोपगि एथलीटों द्वारा प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये कुछ नषिदिध पदार्थों का सेवन है।

वधियक की मुख्य वशिषताएँ:

- वधियक एथलीटों, एथलीट सपोर्ट कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को खेल में डोपगि में शामिल होने से रोकता है।
 - सहायक कर्मियों में कोच, प्रशकिषक, प्रबंधक, टीम स्टाफ, चकित्सिा कर्मी और एथलीट के साथ काम करने या उसका उपचार करने या उसकी सहायता करने वाले अन्य व्यक्ती शामिल हैं।
 - इन व्यक्तियों को यह सुनश्चिति करना चाहिये कि एंटी-डोपगि नयिमें का कोई उल्लंघन न हो जसिमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - कसिी एथलीट के शरीर में प्रतबिंधति पदार्थों या उसके मार्करों की मौजूदगी।
 - कसिी प्रतबिंधति पदार्थ या पद्धतियों का इस्तेमाल।
 - सैपल देने से इंकार करना।
 - प्रतबिंधति पदार्थ या पद्धतियों की तस्करी या तस्करी का प्रयास।
 - ऐसे उल्लंघनों की सहायता करना या उन्हें छपाना।
- **कार्य:**
 - डोपगि रोधी गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनकी नगिरानी करना।
 - डोपगि रोधी नयिमें के उल्लंघन की जाँच।
 - डोपगि रोधी अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- समतिने कहा कि वधियक नाबालगि और वयस्क एथलीटों के बीच अंतर नहीं करता है।
- इसने सफिरशि की कि नाबालगि एथलीटों हेतु एक सुरक्षितमक तंत्र सुनश्चिति करने के लिये नयिमें में एक नाबालगि और वयस्क एथलीट के बीच अंतर कयि जाना चाहिये।
- डोपगि रोधी नयिमें में क्या जोड़ा गया है:
 - खेलों में भाग लेने वाले या संलग्न 'अन्य व्यक्ती'।
 - नरिधारति तरीके के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 'संरक्षति व्यक्तियों' के रूप में नरिदषिट व्यक्ती।
- वशिष डोपगि रोधी एजेंसी संहति के अनुसार, एक संरक्षति व्यक्तीविह

- जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है
- जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है और उसने ओपन श्रेणी में किसी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में भाग नहीं लिया है।
- अपने देश के कानूनी ढाँचे के अनुसार उसमें कानूनी क्षमता का अभाव है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA):

- वर्तमान में राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी एंटी डोपिंग नियमों को लागू करती है। यह एजेंसी सोसायटी के तौर पर स्थापित है।
- वधियक इस राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित करने का प्रावधान करता है।
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त डायरेक्टर जनरल एजेंसी के प्रमुख होंगे।

मध्यस्थता वधियक, 2021

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मध्यस्थता वधियक, 2021 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- वधियक मध्यस्थता (ऑनलाइन मध्यस्थता सहित) को बढ़ावा देने का प्रयास करता है तथा मध्यस्थता समझौते के परिणामस्वरूप नपिटारे को लागू करने का प्रावधान करता है।

मध्यस्थता:

- मध्यस्थता एक स्वैच्छिक, बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें एक नषिपक्ष और तटस्थ मध्यस्थ विवादित पक्षों के बीच समझौता कराने में मदद करता है।
- मध्यस्थता एक प्रकार का वैकल्पिक विवाद समाधान है क्योंकि वे मुकदमेबाजी का विकल्प प्रदान करते हैं।
- मध्यस्थ विवाद का कोई समाधान प्रदान नहीं करता है बल्कि एक अनुकूल वातावरण बनाता है जिसमें विवादित पक्ष अपने सभी विवादों को हल कर सकते हैं।

समिति की प्रमुख टिप्पणियाँ और सफ़ारिशें:

पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता:

- वधियक पक्षों के लिये कम-से-कम दो मध्यस्थता सत्रों में भाग लेना अनिवार्य करता है। अगर वे बना किसी कारण, सत्रों में भाग नहीं लेते तो उन्हें लागत (कोस्ट्स) वहन करनी पड़ सकती है।
 - समिति ने कहा कि पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता को अनिवार्य करने से पक्षों को कई महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा और फरि उन्हें अदालत या ट्रिब्यूनल से संपर्क करने की अनुमति मिलेगी। इससे मामले लंबित हो सकते हैं।
- समिति ने सुझाव दिया कि पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता पर विचार किया जाए, उसे वैकल्पिक बनाया जाए और उसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए।
 - वधियक में यह प्रावधान भी है कि ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों पर पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता को लागू किया जाए।
 - समिति ने कहा कि इस बारे में भी स्पष्टता का अभाव है कि ऐसे मामले पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता के दायरे में कैसे आ सकते हैं।

मध्यस्थता की समय-सीमा:

- पैनल ने समय-सीमा को 180 दिनों से घटाकर 90 दिन करने और 180 दिनों के बजाय 60 दिनों की वसतिार अवधि की सफ़ारिश की।

प्रक्रियाओं की गोपनीयता:

- मध्यस्थता प्रक्रियाओं में शामिल पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन प्रक्रियाओं से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखेंगे।
- समिति ने कहा कि गोपनीयता का उल्लंघन करने पर कोई दंड/दायित्व नहीं है।
- समिति ने सुझाव दिया कि वधियक में गोपनीयता के उल्लंघन के मामलों से जुड़ा प्रावधान होना चाहिये।

समझौतों का पंजीकरण:

- वधियक में मध्यस्थ नपिटान समझौतों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है।
- समिति ने कहा कि पंजीकरण को पक्षों के विकधीन छोड़ देना चाहिये।

ऊर्जा

अक्षय खरीद और ऊर्जा भंडारण दायित्व

ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022-30 की अवधि के लिये अक्षय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation- RPO) और ऊर्जा भंडारण दायित्व (Energy Storage Obligation- ESO) के लिये प्रक्षेपवक्र अधिसूचित किया।

- RPO वदियुत वतियरुण कंननयिं के दायतिय को अकषय स्रोतों से न्यूनतम प्रतशित बजिली की खरीद के लिये संदरभति करता है।
- ESO ऊर्जा भंडारण सुवधि के माध्यम से पवन या सौर से बजिली का न्यूनतम प्रतशित स्रोत के दायतिय को संदरभति करता है।

अकषय ऊर्जा:

- प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा जो उपयोग की गई ऊर्जा से अधिक तेजी से भरती है, उसे अकषय ऊर्जा कहा जाता है।
- ऐसे स्रोतों के उदाहरण जनिकी लगातार पूरत होती रहती है, वे हैं धूप और हवा। हमारे लिये कई प्रकार की अकषय ऊर्जा उपलब्ध हैं।
- नवीकरणीय स्रोतों से वदियुत का उत्पादन करने की तुलना में जीवाश्म ईंधन को जलाने से अधिक उत्सर्जन होता है।

इन दायतियों को पूरा करने के लिये प्रमुख शर्तें:

- **पवन और जल नवीकरणीय खरीद दायतिय (RPO):**
 - कुल RPO में से एक नश्चिति प्रतशित पवन और जल स्रोतों से पूरा किया जाना चाहिये।
 - पवन RPO के लिये केवल मार्च 2022 के बाद चालू हुई परयोजनाओं से प्राप्त बजिली पर ही वचियर किया जाएगा।
 - हाइड्रो RPO के लिये मार्च 2019 के बाद चालू बड़ी पनबजिली परयोजनाओं से प्राप्त बजिली पर ही वचियर किया जाएगा। RPO के लिये आयातित जल वदियुत पर वचियर नहीं किया जाएगा।
- **राज्य आयोगों से बजिली:**
 - राज्य बजिली नयियमक आयोग मंत्रालय द्वारा नरिदषिट लक्ष्य से अधिक RPO और ESO नरिदषिट कर सकते हैं।

शकिया

उच्च शकिया संस्थानों की समीक्षा

शकिया, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समतिने 'डीमड/नजी वशिववदियालयों/अन्य उच्च शकिया संस्थानों में शकिया मानकों की समीक्षा, मान्यता प्रक्रिया, अनुसंधान, परीक्षा सुधार और शैक्षणिक वातावरण की समीक्षा' पर अपनी रपिर्ट प्रस्तुत की।

समति के मुख्य नषिकर्ष और सुझाव:

भारतीय उच्च शकिया आयोग (HECI):

- राष्ट्रीय शकिया नीति (NEP), 2020 में उच्च शकिया के लिये मुख्य नयियमक के रूप में HECI के गठन का प्रावधान है।
 - समतिने कहा कि HECI के प्रावधान वाला वधियक अभी ड्राफ्टिंग के चरण में है।
- समतिने सुझाव दिया कि HECI का नरिमाण करते समय, इसके कषेत्राधिकार, स्वतंत्रता और हतिधारकों के हतियों की सुरक्षा को नरिदषिट करने से संबंधित पहलुओं पर वचियर किया जाना चाहिये।
- उच्च शकिया के लिये कई समानांतर नयियमक प्राधकिरण के बजाय नयिमों/रेगुलेशंस/अधनियिम के कार्यान्वयन में अंतमि फ़ैसला देने वाले नयियमक नकियों का सहज पदानुक्रम (हेरारकी) बनाया जाना चाहिये।

राज्य वशिववदियालयों में परीक्षा:

- समतिने कहा कि राज्य वशिववदियालयों को परीक्षाएँ संचालित करने में समस्याएँ होती हैं। इन समस्याओं में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - प्रश्न पत्र लीक होना।
 - नकल के अनयित्तरति मामलें।
 - वदियार्थयिं और परीक्षकों की मलीभगत।

समतिने सुझाव दिया कि मान्यता देते समय, संस्थान की परीक्षा प्रबंधन क्षमता पर वचियर किया जाना चाहिये। परीक्षा की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को अपनाने को प्रोत्साहति किया जा सकता है।

सामाजिक वज्जान और तकनीकी शकिया:

- समतिने सुझाव दिया कि तकनीकी संस्थानों में ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स शुरू करने का प्रयोग किया जाए और इस बात का आकलन किया जाए कि संस्थान के शैक्षणिक परविश पर उसका क्या असर होता है। इसके अतरिकित सोशल साइंस/ह्यूमैनिटीज़/आर्ट मॉड्यूलस को तकनीकी शकिया के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिये।

उपभोक्ता मामले

सेवा शुल्क लगाने के नषिध पर दशिया-नरिदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधकिरण (CCPA) ने अनुचति व्यापार प्रथाओं से बचने और सेवा शुल्क का आकलन करने वाले होटलों और रेस्तराँ में उपभोक्ता

इतियों की रक्षा के लिये नयिम जारी कयि हैं ।

CCPA की प्रमुख टपिणयिाँ

- CCPA ने कहा कि टपि या ग्रेच्युटी उपभोक्ता की मरजी से दी जाती है ।
- उसने यह भी कहा कि सरवसि के हसिसे में परोसे गए खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ की कीमत शामिल है, यानी उत्पाद की कीमत में सामान और सेवाओं, दोनों का घटक शामिल है ।
 - खाने-पीने की चीजों के दाम तय करने के लिये होटल और रेस्तराँ पर कोई रोक नहीं है ।
- CCPA के अनुसार, लागू करों के साथ उत्पाद की उक्त कीमत के अलावा कुछ भी चार्ज करना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है ।
- अगर सरवसि चार्ज लगाया जाता है या उपभोक्ता को इसका भुगतान करने के लिये मजबूर किया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन या उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की जा सकती है ।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

- इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA) 2019 के तहत स्थापित किया गया था ।
- यह एक वैधानिक निकाय है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत काम करता है ।

उद्देश्य:

- एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना ।
- उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना और शिकायत/अभियोजन करना ।
- असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापसी, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं भ्रामक वजिजापनों को बंद करने का आदेश देना ।
- भ्रामक वजिजापनों के निर्माताओं/प्रदर्शकों/प्रकाशकों पर दंड लगाना ।

दिल्ली HC द्वारा सेवा शुल्क पर लगाए गए प्रतिबंध

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने दशा-नरिदेशों पर इस आधार पर रोक लगा दी कि सेवा शुल्क लगाना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार के बराबर नहीं हो सकता ।
 - अधिनियम के अनुसार, अनुचित व्यापार व्यवहार का अर्थ है, वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिये अनुचित तरीके या भ्रामक पद्धतियों को अपनाना ।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सेवा शुल्क लगाया जा सकता है, लेकिन इसे मैन्यू या अन्य स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिये जहाँ यह समीचीन हो सकता है ।
 - इसके अलावा टेकअवे के मामले में ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है ।

गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने 'गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष (Quality Control Cells- QCC)' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **अधिक QCC की आवश्यकता:**
 - खरीद से वितरण तक खाद्यान्न स्टॉक के केंद्रीय पूल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये QCC ज़िम्मेदार हैं ।
 - वर्तमान में देश में 11 QCC हैं ।
 - समिति ने कहा कि QCC की संख्या अपर्याप्त है ।
 - उसने गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित करने और क्षतग्रिस्त खाद्यान्नों के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिये और अधिक QCC स्थापित करने का सुझाव दिया ।
- **शिकायत निवारण:**
 - समिति ने कहा कि लाभार्थियों को घटिया गुणवत्ता का खाद्यान्न मिलने की कई शिकायतें मिली हैं ।
 - इसके अलावा यह देखा गया कि लाभार्थियों की दिनि-प्रतदिनि की समस्याओं को हल करने में हेल्पलाइन नंबर अप्रभावी रहे हैं ।
 - समिति ने इन हेल्पलाइन नंबरों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने की सफिराशि की । उसने यह सुझाव भी दिया कि:
 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग या कसिी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर स्वतंत्र औचक नरीक्षण किया जाए ।
 - इन दुकानों पर PDS वस्तुओं के वितरण और डायवर्जन की नगिरानी के लिये उचित मूल्य की दुकानों की CCTV नगिरानी की जाए ।

प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016 में संशोधनों को अधिसूचित किया।

- नयिम प्लास्टिक से उत्पादित सामग्री (जैसे- बैग और पैकेजिंग सामग्री) के निर्माण और बिक्री के लिये मानक निर्धारित करते हैं।
- नयिम प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन के लिये रूपरेखा भी निर्दिष्ट करते हैं।

संशोधनों की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

■ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक:

- संशोधन में कहा गया है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के निर्माताओं/विक्रेताओं को विपणन या बिक्री से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिये।
- इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित और CPCB द्वारा प्रमाणित मानकों के अनुरूप होना चाहिये।
- संशोधनों में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को प्लास्टिक (खाद योग्य प्लास्टिक के अलावा) के रूप में परिभाषित किया गया है जो पर्यावरण के लिये हानिकारक अवशेषों को छोड़े बिना जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरता है।

■ पर्यावरणीय कषतपूरत:

- संशोधनों में कहा गया है कि CPCB द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर पर्यावरणीय कषतपूरत लगाई जाएगी।

■ केंद्रशासित प्रदेशों में नयिमों का कार्यान्वयन:

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board- SPCB) और प्रदूषण नियंत्रण समिति (Pollution Control Committee- PCC) केंद्रशासित प्रदेशों में नयिमों को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार हैं। संशोधन में कहा गया है कि केंद्रशासित प्रदेशों में नयिमों को लागू करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी ज़िम्मेदार होगा।

■ निर्माताओं का पंजीकरण:

- कैंरी बैग, रीसाइकल प्लास्टिक बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग के निर्माताओं को SPCB या UT के PCC से पंजीकरण प्राप्त करना होगा। संशोधन में प्रावधान है कि ऐसे निर्माताओं को नमिनलखिति से पंजीकरण प्राप्त करना होगा:
 - केंद्रशासित प्रदेश के SPCB/PCC, अगर एक या दो राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में काम कर रहे हैं
 - CPCB, अगर दो से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में काम कर रहे हैं।